## Need to take initiative by India at the ensuing Ministerial Conference of the W.T.O. at Doha to evolve a common strategy to safeguard the vital interests of the Developing Countries

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala): Sir, the ensuing Ministerial Conference of the World Trade Organisation at Doha is very crucial for the developing countries, including India. The United States and the European \* Union are putting every sort of pressure on the developing countries to start a new round of trade negotiations. They insist on a new round, to include labour, environment and other issues, in -favour of the developed, rich, countries. Whereas the developing countries' immediate interest lies in implementing properly the existing agreements, the USA and the European Union often put obstacles to market access, on flimsy grounds. The agreement on agriculture and the TRIPS Agreement are twisted in their favour. The livelihood issue of the poor countries is completely ignored. The most important thing for the developing countries is to rectify these issues. To resist all sorts of pressures from the developed countries and to evolve a common strategy to safeguard the vital interests of the developing countries, India should take a diplomatic initiative to unify all the developing countries. We were in the forefront of the Non-Aligned Movement. This is the time, once again, for us to play the role which none else could do.

## Reforming Graphite Industries in Sivaganga District of Tamil Nadu

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Sir, I rise to speak on reforming the graphite industries and its ancillary units in and around Kumarapatti and Komalipatti of Sivaganga District, the industrially backward area of Tamil Nadu. Valuable minerals for graphite industries are available in these areas. After conducting so many tests, the then Government, under the leadership of Dr. M.G.R., acquired the required land after paying the necessary compensation. The foundation stone was laid by the former Prime Minister, late Rajiv Gandhi, in the year 1989. This graphite ore is equivalent to the ore available in Japan. The Government had allotted Rs. 22 crores for the purification of the graphite ore available in those areas. A factory was set up for this purpose. After that, the Tamil Nadu Mineral Corporation took charge of this graphite industry, and they are simply selling the raw material. The Tata Consultancy to whom this matter was referred for opinion, opined that more than four ancillary units may be started in this area by using this graphite ore. This graphite ore is used for manufacturing of aircraft parts, carbon, boilers, etc. By using this graphite, there is a possibility of starting so many ancillary units in and around Sivaganga district which would

provide employment opportunities to the people of those areas. I request the Central Government to come forward to make the necessary allotment of funds for this project in order to have an industry in this backward area of Tamil Nadu, which would provide employment opportunities to the people of that area.

## Department of Personnel and Training Circulars on Roster System

श्री राजू परमार (गुजरात): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और आदरणीय प्रधान मंत्री जी की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने 1997-98 में कोर्ट के जजमेंट के आधार पर जो पांच ऑफिस मेमोरंडम इश्यू किए हैं उसकी वजह से पूरे देश के एस.सी.एस.टी एम्प्लोइज के हक पर हमला हुआ है। उनके प्रमोशन बंद हो गए हैं, रिक्रूटमेंट बंद हो गया है और संविधान में जो रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत राइट्स मिल रहे थे उस पर पूरा अमल नहीं हो रहा है। तो मैं खास तौर से जो पांच सर्क्यूलर डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल ने इश्यू किए उनमें से दो सर्क्यूलर अभी विद्झा हो गए है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।...(यवधान)...

श्री रिव शंकर प्रसाद (बिहार): पढ़ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ? ...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार (गुजरात): आप अगेंस्ट में हो तो आप अगेंस्ट में बोल दीजिएगा । ...(व्यवधान)... तभी तो दलित आप से दूर हो रहे हैं । ...(व्यवधान)... दलितों के मामले में भी आप विरोध कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश)ः सभापति जी , की अनुमति है तो ठीक है।...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार (गुजरात)ः हां अनुमित है। ...(व्यवधान)... आप बोलिए विरोध में बोलना है तो सर, मैं आपके माध्यम से इस हाउस के जिरए से आदरणीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दो सरकुलर विदड़ा हुये हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू नहीं हुआ है और वे वहीं के वहीं हैं। बाकी के जो तीन सरकुलर हैं, 30 जनवरी 1997, 2 जुलाई, 1997 और 13 अगस्त, 1997 के उनको अभी विद्ड़ा करना है प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट को दोनों सदनों को और हाउस के बाहर भी बार बार एश्योरेंस दिलत फोरम को एस.सी/एस.टी एम्पलाइज को दिया है कि इन सरकुलरों को जल्दी से जल्दी विद्ड़ा किया जायेगा लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद भी स्थिति वहीं की वहीं है। पूरे देश में एस.सी/एस.टी. के एम्पलाइज नाराज हैं और इससे प्रभावित है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी कि ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन तीन सरकुलरों को जो एस.सी/एस.टी के रिजर्वेशन पालिसी के खिलाफ हैं, पूरे एस.सी/एस.टी के लोग प्रभावित हैं, उनको विद्ड़ा किया जाये। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि इनको संसद का सत्र खत्म होने से पहले निश्चित अवधि में विद्ड़ा किया जाये।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, एक निश्चित समय सीमा के अंदर सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और इसको गम्भीरता से लेना चाहिए।...(व्यवधान)...